

कायदे, कानून व प्रक्रिया की पूरी जानकारी न होना भारी पड़ रहा है, भाजपा पर संसद में

जो हश्र “प्रिवलेज मोशन” का हुआ, वह ही अंजाम राहुल को डिस्क्वालिफाई करने के हल्ले का होगा?

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 फरवरी। भाजपा और निशिकांत दुबे विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संसद से डिस्क्वालिफाई करने की मांग करके देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की धमकी दी थी। लेकिन यह धमकी इसलिए वापस ले ली गई, क्योंकि लोकसभा की विशेषाधिकार समिति अभी तक गठित ही नहीं हुई है। संभव है कि रिजिजू को भी इस बात की जानकारी नहीं थी।

विशेषाधिकार प्रस्ताव के लिए एक तय प्रक्रिया और नियम होता है। पहले विशेषाधिकार समिति अपनी रिपोर्ट देती है। इसके बाद मामला आचार समिति (एंथिक्स कमेटी) के पास जाता है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसलिए प्लान बी के तौर पर निशिकांत दुबे को आगे किया गया।

- “प्रिवलेज मोशन” नहीं लाया गया, क्योंकि “प्रिवलेज कमेटी” का अभी तक गठन नहीं हुआ है। प्रिवलेज कमेटी प्रस्ताव का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट देती है, जो “एंथिक्स कमेटी” के सामने प्रस्तुत होती है। “एंथिक्स कमेटी” की सिफारिश के बाद, निर्णय लिया जाता है, किसी व्यक्ति के खिलाफ “प्रिवलेज मोशन” लाया जाए या नहीं। जब “प्रिवलेज कमेटी” का गठन ही नहीं हुआ अभी तक, तो “प्रिवलेज मोशन” की कार्यवाही आगे कैसे बढ़ती।
- इसी प्रकार निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को “डिस्क्वालिफाई” करने की मुहिम शुरू की। पर, यह स्पष्ट नहीं था कि राहुल गांधी को किस “रूल” के अंतर्गत “डिस्क्वालिफाई” करने की मांग की जा रही है या किस प्रक्रिया के जरिए राहुल गांधी को डिस्क्वालिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है।
- निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायतों की लाइन लगा दी, शून्यकाल में। पर, ये शिकायतें किसी भी “लैटर हैड” पर नहीं लिखी गई थीं तथा शिकायत पत्र पर किसी भी सांसद के हस्ताक्षर नहीं थे तथा यह भी स्पष्ट नहीं था कि यह शिकायत पत्र किस के पास भेजा जाए।

उन्होंने मांग की कि राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया जाए। लेकिन किस प्रस्ताव के तहत? किस नियम के तहत? किस प्रक्रिया के तहत? खुद सांसद को ही इसकी

जानकारी नहीं है। उन्होंने विपक्ष के नेता के खिलाफ शिकायतों की लंबी सूची लिखी और उसे शून्य काल में पढ़कर सुना दिया। जिस कागज पर शिकायत लिखी

गई, वह न तो कोई लेटरहेड था और न ही उस पर कोई हस्ताक्षर। यह शिकायत किसे संबोधित की गई थी? किसी को भी इसकी जानकारी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सावलकोट पावर प्रोजैक्ट पर काम शुरू होने से घबराया पाकिस्तान

पाकिस्तान ने फिर से भारत पर पानी रोकने का आरोप लगाया

-श्रीरंज झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 फरवरी। भारत-पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल कम होता नज़र नहीं आ रहा है और आने वाले समय में भी इसके शांत होने की संभावना कम दिखती है।

पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पर इस्लामाबाद के खिलाफ “पानी रोकने की नीति” अपनाने का आरोप लगाया है। वहीं, भारत का कहना है कि उसे अपने क्षेत्र के अंदर बुनियादी ढांचा बनाने और सिंधु नदी की सहायक नदियों के बेहतर प्रबंधन का पूरा संप्रभु अधिकार है।

पाकिस्तान की ताजा आपत्ति चिनाब नदी पर 5 129 करोड़ रुपये की लागत वाली सावलकोट जलविद्युत परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होने की खबरों के बाद सामने आई है। पाकिस्तान ने कहा है कि वह भारत की

- भारत सरकार ने कहा, उसे अपने क्षेत्र में नदियों पर इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का पूरा अधिकार है। इसके लिए किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।
- इधर पाकिस्तान ने कहा कि उसकी पानी की तीन चौथाई जरूरत चिनाब जैसी नदियों से पूरी होती है, और भारत द्वारा बाँध बनाने से उसका पानी रुक जाएगा।
- ज्ञातव्य है कि भारत सरकार ने चिनाब पर 5129 करोड़ रूपए की लागत से सावलकोट पन बिजली योजना शुरू की है।

इस कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय कानूनी मंचों पर चुनौती देगा। पहलगाम हत्याकांड और उसके बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। इसके बाद भारत ने जम्मू-कश्मीर में कई जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण शुरू किया है और कहा है कि अपने बुनियादी ढांचे का प्रबंधन

करना उसका संप्रभु अधिकार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज कहा कि देश के भीतर शुरू की गई किसी भी विकास परियोजना का फैसला हमारी अपनी समझ के आधार पर होता है। नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा सावलकोट बांध, सिंधु जल संधि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बांग्लादेश चुनावों से गायब हैं महिला नेता

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 फरवरी। बांग्लादेश के चुनावी परिदृश्य में नाटकीय बदलाव आया है। कभी शेख हसीना और खालिदा ज़िया जैसी प्रभावशाली महिला नेताओं से पहचाने

- शेख हसीना और खालिदा ज़िया जैसी सशक्त महिला नेताओं का नेतृत्व देख चुके बांग्लादेश के आम चुनावों में मात्र 4 प्रतिशत महिलाएं ही चुनाव मैदान में दिखीं।

जाने वाले देश में अब मतपत्रों पर महिलाएं लगभग नदारद हैं। देशभर में केवल 4 प्रतिशत उम्मीदवार महिलाएं हैं, जिनमें से कई केवल पुरुष नेताओं से जुड़ी प्रतीकात्मक उम्मीदवार मानी जा रही हैं।

जहां कुछ इस्लामी दलों ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी फिल्म “घूसखोर पंडित” का नाम बदलने का नोटिस दिया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी फिल्म “घूसखोर पंडित” के निर्माताओं को इसके कथित जातिसूचक शीर्षक को लेकर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि “फिल्म का नया नाम बताइए, नहीं तो रिलीज की अनुमति नहीं दी जाएगी।”

नीरज पांडे द्वारा निर्देशित और मनोज बाजपेयी अभिनीत फिल्म

- सुप्रीम कोर्ट ने माना कि फिल्म का नाम ब्राह्मण भावनाओं को आहत करता है। कोर्ट ने कहा, इसे बदलें, वरना रिलीज की अनुमति नहीं मिलेगी।

“घूसखोर पंडित” नैटफ्लिक्स पर रिलीज की घोषणा के बाद विवादों में घिर गई है। आरोप है कि फिल्म का शीर्षक ब्राह्मण समुदाय की भावनाओं को आहत करता है। अंग्रेजी में अनुवाद करने पर इस शीर्षक का मतलब एक भ्रष्ट ब्राह्मण होता है।

फिल्म निर्माताओं की ओर से पेश वकील ने अदालत को भरोसा दिलाया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हिंसा व हत्याओं के वातावरण में बांग्लादेश में चुनाव सम्पन्न

पिछले चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी व जमात-ए-इस्लामी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के खिलाफ

- अब शेख हसीना की पार्टी चुनाव क्षेत्र में नहीं है, अतः बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी व जमात-ए-इस्लामी आमने-सामने मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं।
- भारत के लिए एक तरफ खड़ा और दूसरी तरफ खाई है, क्योंकि दोनों ही भारत विरोधी पार्टियां हैं, तथा बांग्लादेश से हिंदुओं को बाहर निकालकर फैंकना चाहती हैं। अजीबोगरीब बात है, जब बांग्लादेश, पाकिस्तान का हिस्सा था और पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, जब हिंदू विरोधी हिंसा व वारदातें कम होती थीं। ये घटनाएं अब कई गुना बढ़ गई हैं।
- बहरहाल, बांग्लादेश में वर्तमान गरीबी व कानून व्यवस्था भारत के लिए भारी संकट पैदा कर रही है, क्योंकि इस निर्धनता व बेरोज़गारी के कारण भारत के लिए पलायन करने वाले बांग्लादेशियों की संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है और भारत के लिए संकट व सुरक्षा का मुद्दा और गंभीर बनाता जा रहा है।

से भी रोक दिया गया।

इसके बजाय, विभिन्न स्तरों की

कट्टरपंथी सोच वाले राजनीतिक दलों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा

लोकसभा सचिवालय ने कहा, ऐसा कोई प्रस्ताव विचार के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है

- विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं लाए जाने पर यह चर्चा भी है कि स्पीकर के कार्यालय ने ऐसी कोई प्रक्रिया शुरू करने से खुद का अलग कर लिया है।
- गुरुवार सुबह भी संसद का माहौल उस समय काफी उग्र हो गया, जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराने की मांग कर दी।
- लेकिन शाम तक माहौल ठंडा पड़ चुका था, जब यह पता लगा कि न तो विशेषाधिकार प्रस्ताव का औपचारिक आवेदन आया है, न ही राहुल को “डिस्क्वालिफाई” करने का प्रस्ताव आया है।
- राजनैतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि सत्ता पक्ष का पीछे हटना उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि रणनीतिक कदम है। भले ही भाजपा राष्ट्रीय राजनीति में हावी है, पर, संसद में उसके पास प्रचंड बहुमत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को डिस्क्वालिफाई करना न केवल उन्हें हीरो बना सकता है, बल्कि सहयोगी दलों को भी नाराज़ कर सकता है।

कड़ा राजनीतिक हमला भी शामिल था, गांधी ने कथित तौर पर तथाकथित “एस्पर्टोन फाइल्स” और उसके अंतरराष्ट्रीय संपर्कों का उल्लेख किया। सत्तापक्ष के सदस्यों के अनुसार, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों की सीमा को स्पर्श कर रहा था। इसके तुरंत बाद, उनके भाषण के महत्वपूर्ण हिस्सों को संसदीय अभिलेखों से हटा दिया गया, और यह कदम स्वयं एक राजनीतिक विवाद का कारण बन गया।

गुरुवार सुबह राजनीतिक माहौल तब और गरमा गया, जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, जो अपने आक्रामक तेवरों के लिए जाने जाते हैं, को कथित तौर पर गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपे जाने की खबरें आईं। सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों का तर्क (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कक्षा-10 की परीक्षा का फॉर्मेट बदला

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 फरवरी। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे संशोधित प्रश्नपत्र पैटर्न से परिचित होने के लिए सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकण्डरी

- सीबीएसई ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि नए फॉर्मेट को समझने के लिए सीबीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञान व सामाजिक ज्ञान के नमूना प्रश्न पत्र को हल करें।

एजुकेशन (सीबीएसई) की शैक्षणिक वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के नमूना प्रश्नपत्रों का अध्ययन करें।

सीबीएसई ने कक्षा 10 की बोर्ड (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

हम यहाँ किसी विशेष कारण से हैं। इसीलिए अपने भूत का कैदी बनना छोड़िये। अपने भविष्य के निर्माता बनिएं। –रोबिन शर्मा

दस पिल्लरों के मजबूत आधार से लिखी जा रही 2047 के राजस्थान की इबारत

वैसे तो यह परंपरा रही है कि किसी भी सरकार का बजट हो और कितना ही विजनरी बजट हो पर सत्ता पक्ष उसके गुणगाण में लगता है तो विपक्ष कमियाँ ही कमियाँ देखने में जुट जाता है। इसलिए विल्टमंजी दिया कुमारी के 2 घंटे 54 मिनट के 143 पेज के बजट को लेकर आलोचना-प्रत्यालोचना से अलग हटकर देखना ही सही मायने में उसके साथ न्याय हो सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के तीसरे बजट में खास बात यह है कि यह बजट दूरगामी सोच यानी कि 2047 की राजस्थान की इबारत लिखने का बढ़ता कदम है। इस बजट की विजनरी बजट इस मायने में कहा जा सकता है कि पहली बार किसी बजट को समग्रता से रखा गया है। भजनलाल सरकार ने बजट को प्रदेश के समग्र विकास की दृष्टि से दस पिल्लरों का ठोस आधार दिया है। इसे यों भी समझा जा सकता है कि प्रदेश के विकास के दस पिल्लरों से 2047 के राजस्थान का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। पिल्लर्स भी इस तरह से तैयार किये गये हैं जिससे किसी तरह के संदेह की गुंजाइस नहीं रह जाती है। आधारभूत संरचना से लेकर 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनोमी का रोडमैप इस बजट में देखा जा सकता है।

राजस्थान की सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट को 10 पिल्लरों का आधार दिया है। वैसे तो सभी दस पिल्लर्स अपने आपमें अपना महत्व रखते हैं पर जिस तरह से इन पिल्लरों को प्राथमिकता दी गई है उससे यह साफ हो गया है कि प्रदेश के विकास का सशक्त आधार तय करने पर जोर दिया गया है। बजट में पहला पिल्लर इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तार का है तो अन्य पिल्लरों में क्रमशः नागरिक सुविधाओं में गुणात्मक जीवन स्तर में सुधार, औद्योगिक विकास और निवेश प्रोत्साहन, मानव संसाधन सशक्तिकरण, सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, पर्यटन, कला सांस्कृतिक धरोहर, सुशासन-डिजिटल परिवर्तन, कृषि विकास-किसान कल्याण, हरित विकास-पर्यावरण सततता और आखिरी व 10 वां पिल्लर 2047 का राजस्थान का है। देखा जाएं तो यह सभी दसों पिल्लर राजस्थान और राजस्थानवासियों के समग्र विकास और प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को चरणबद्ध रुप से गति देने वाले होने के साथ ही विकसित राजस्थान, शिक्षित राजस्थान, निरोगी राजस्थान, समृद्ध किसान-और खेती, औद्योगिक विकास, रोजगार और स्वरोजगार के विपुल अवसर, खनन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीरता की दर्शाता है। खास बात यह है कि प्रदेश के बजट में अरावली संरक्षण के प्रति दर्द भी है तो संरक्षण के प्रति गंभीरता भी स्पष्टता दिखाई देती है।

देखा जाएं तो यह सभी दसों पिल्लर राजस्थान और राजस्थानवासियों के समग्र विकास और प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को चरणबद्ध रुप से गति देने वाले होने के साथ ही विकसित राजस्थान, शिक्षित राजस्थान, निरोगी राजस्थान, समृद्ध किसान-और खेती, औद्योगिक विकास, रोजगार और स्वरोजगार के विपुल अवसर, खनन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। खासबात यह है कि प्रदेश के बजट में अरावली संरक्षण के प्रति दर्द भी है तो संरक्षण के प्रति गंभीरता भी स्पष्टता दिखाई देती है।

आधारभूत सुविधाएं और बेहतर कानून व्यवस्था किसी भी देश या प्रदेश में निर्बाध उपलब्ध होती है तो विकास की राह अपने आप खुलने लगती है। देशी-विदेशी निवेश आने लगता है तो औद्योगिक विकास से रोजगार और आय के साधन विकसित होते हैं। सांस्कृतिक धरोहरों को संजोने से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और इससे इकोनोमी को बूस्ट मिलता है। सबसे बड़ी बात तो यह कि जब समग्र विकास की रूपरेखा बनती है तो फिर निवासियों के जीवन स्तर में भी सकारात्मक बदलाव आता ही है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजनरी सोच को इस तरह से समझा जा सकता है कि सरकार के पहले साल में ही राइजिंग राजस्थान का आयोजन कर औद्योगिक निवेश के करार किये गये। उसके बाद लगातार मोनेटरिंग का परिणाम है कि ग्राउण्ड ब्रेकिंग के प्रयासों में तेजी आई है। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को मातृभूमि से जोड़ने की जो पहल प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन से की है और अब प्रतिवर्ष इसके आयोजन का निर्णय किया है इसके भी सकारात्मक प्रयास आने ही हैं। क्योंकि प्रवासी राजस्थानियों ने अपने उद्यम कौशल से देश-दुनिया में डंका बजा रखा है और अब सरकार की पहल से इसका लाभ प्रदेश को मिलना ही है। क्योंकि प्रवासी राजस्थानी राजस्थान में आधारभूत सुविधाओं और निवेश अनुकूल माहौल से प्रेरित होकर प्रदेश में निवेश के लिए आगे आयेगी ही और इसका एक बड़ा कारण सरकार का प्रोएक्टिव रोल व दूसरा सरकार द्वारा प्रवासियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ने की भावनात्मक पहल है।

सवाल यह नहीं है कि किस क्षेत्र के लिए कितना बजट दिया गया है या किस क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता दी गई है अपितु यह है कि समग्र रुप से दसों पिल्लर अपने-अपने क्षेत्रों में परफरमेंस दिखाते हैं तो 2047 की सशक्त इमारत तैयार होने से कोई नहीं रोक सकता। राज्य के बजट को इस दृष्टि से भी देखने की आवश्यकता है।

–अतिथि सम्पादक, डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (वरिष्ठ लेखक)

पंडित अनिल शर्मा

राशिफल शुक्रवार 13 फरवरी, 2026

फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, मूल नक्षत्र सायं 4:16 तक, वज्र योग रात्रि 3:23 तक, बालव करण दिन 2:26 तक, चन्द्रमा आज धनु राशि में संचार करेगा।

गृह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-धनु, मंगल-मकर, बुध-कुम्भ, गुरू-मिथुन, शुक्र-कुम्भ, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

कुमार योग सूर्योदय से दिन 2:26 तक है। राजयोग सायं 4:13 से सूर्योदय तक है। आज विजया एकादशी व्रत, संक्रांति पुण्य काल पूर्वान्ह में है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:32 तक, लाभ-अमृत 8:32 से 11:18 तक, शुभ 12:41 से 2:04 तक, चर 4:50 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:09, सूर्यास्त 6:13

मेघ

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटके हुए कार्य बने लगेंगे। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

सिंह

व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। नौकरपेशा व्यक्तियों को उचित सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

वृष

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब होने का भय रहेगा। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

कन्या

घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी। आज समय अनलल कार्यों में खराब होगा। मन में असंतोष बना रहेगा।

मिथुन

परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

तुला

व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

कुंभ

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। वृद्धि होगी। संभावित ख़ोते से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कर्क

व्यक्तिगत परेशानियों से राहत मिलेगी। अनहोनी की आशंका से बचा हुआ मन का भय दूर होगा। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है।

वृश्चिक

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

राजस्थान बजट 2026-27 : सुदृढ़ कानून व्यवस्था से समृद्धि

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट सुरक्षा और समृद्धि के संतुलित समन्वय का दस्तावेज है

ओ. पी. गल्होत्रा

राजस्थान का बजट 2026-27 विकास की रूपरेखा होने के साथ ही सुरक्षित और विश्वासपूर्ण समाज के निर्माण का भी स्पष्ट संकल्प है। किसी भी राज्य की प्रगति का वास्तविक आधार उसकी कानून-व्यवस्था होती है। यदि नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करें, निवेशक निश्चित होकर पूंजी लाएंगे, महिलाएँ और बच्चे भयमुक्त वातावरण में जीवन जी सकें, तभी विकास के सभी आंकड़े सार्थक सिद्ध होते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट सुरक्षा और समृद्धि के संतुलित समन्वय का दस्तावेज है। कुल 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपये के आकार वाला यह बजट न केवल आर्थिक विस्तार की दर्शाता है, बल्कि प्रशासनिक और सुरक्षा तंत्र

के सुदृढ़ीकरण की स्पष्ट दिशा भी देता है। बजट में किए गए प्रावधान प्रदेश में कानून-व्यवस्था को आधुनिक, जवाबदेह और तकनीक-सक्षम बनाने की व्यापक योजना प्रस्तुत करते हैं। बजट में पुलिस बल की संरचनात्मक मजबूती पर जोर दिया गया है। रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती और प्रशिक्षण व्यवस्था के आधुनिकीकरण का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है। लंबे समय से पुलिस बल पर बढ़ते कार्यभार को देखते हुए यह आवश्यक था कि बल की संख्या और क्षमता दोनों में वृद्धि हो। नए पुलिसकर्मियों की नियुक्ति से थानों में लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण होगा और गश्त व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी। इससे अपराध की रोकथाम में प्रत्यक्ष सुधार देखने को मिलेगा।

डिजिटल युग में अपराध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल ठगी जैसे मामलों में वृद्धि के परिप्रेष्य में प्रत्येक संभाग में अत्याधुनिक साइबर क्राइम यूनिट की स्थापना का निर्णय दूरदर्शी कदम है। इससे न केवल अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी में तेजी आएगी, बल्कि आम नागरिकों में डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी।यह पहल दर्शाती है कि सरकार भविष्य की चुनौतियों के लिए वर्तमान में तैयारी कर रही है।

महिला सुरक्षा इस बजट की प्राथमिकताओं में स्पष्ट रूप से

परिलक्षित होती है। प्रत्येक जिले में महिला सहायता डेस्क और विशेष अन्वेषण प्रकोष्ठ की स्थापना से पीड़ित महिलाओं को त्वरित और संवेदनशील सहायता मिलेगी। महिला अपराधों की जांच के लिए समयबद्ध प्रणाली और फास्ट ट्रैक दृष्टिकोण से न्याय की प्रक्रिया में गति आएगी। यह संदेश भी जाएगा कि राज्य सरकार महिला सुरक्षा के प्रश्न पर किसी प्रकार की हिलाई बरतने के पक्ष में नहीं है।

पुलिस थानों के आधुनिकीकरण और डिजिटल केस मैनेजमेंट प्रणाली का विस्तार कानून-व्यवस्था में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। सीसीटीवीएनएस के उच्चम और डेटा इंटीग्रेशन से अपराधियों का ट्रैक रिकॉर्ड तुरंत उपलब्ध होगा, जिससे अपराधनियंत्रण की प्रक्रिया अधिक सटीक और त्वरित बनेगी। संवेदनशील क्षेत्रों में स्मार्ट सर्बिलॉस और सीसीटीवी नेटवर्क का विस्तार सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी व्यवस्था को मजबूत करेगा, जिससे अपराध की संभावनाएँ स्वतः कम होंगी। समुदायिक पुलिसिंग को प्रोत्साहन देने का निर्णय भी उल्लेखनीय है। कानून-व्यवस्था केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक चेतना का परिणाम होती है। नागरिकों और पुलिस के बीच संवाद को मजबूत कर विश्वास का वातावरण बनाया जा सकता है। समुदायिक सहभागिता से स्थानीय स्तर पर विवादों का समाधान शीघ्र

होगा और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगेगा।

पुलिस कमियों के आवास, कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रमों के लिए विशेष प्रावधान भी इस बजट की संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। निरंतर दबाव में कार्य करने वाले पुलिस बल के मनोबल को बनाए रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराना। जब बल संतुष्ट और प्रेरित होगा, तो उसका प्रदर्शन भी बेहतर होगा। इन सभी पहलों का परिणाम प्रदेश की समग्र कानून-व्यवस्था की स्थिति में स्पष्ट सुधार के रूप में सामने आया है। संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और महिला अपराधों के मामलों में सख्त कार्रवाई से अपराधियों में भय और नागरिकों में विश्वास का वातावरण बना है। निवेशकों के लिए सुरक्षित माहौल उपलब्ध होने से औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ी हैं और पर्यटन क्षेत्र में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

विकास और सुरक्षा परस्पर पूरक हैं। जब राज्य की सकल घरेलू उत्पाद 21 लाख 52 हजार करोड़ रुपये से अधिक पहुँचने का अनुमान हो, प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो, शिक्षा और स्वास्थ्य पर रिकॉर्ड निवेश हो, तो यह सब तभी सार्थक है जब समाज सुरक्षित हो। 53 हजार 978 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय, शिक्षा के लिए 69 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान और स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़े

निवेश भी अंततः उसी सामाजिक स्थिरता पर निर्भर करते हैं, जिसकी नींव मजबूत कानून-व्यवस्था से पड़ती है।

कृषि, जल प्रबंधन और महिला सशक्तिकरण जैसी योजनाएँ सामाजिक असमानताओं को कम करती हैं और इससे अपराध के सामाजिक कारणों में कमी आती है। युवाओं को रोजगार के अवसर, पारदर्शी भर्ती प्रणाली और कौशल विकास कार्यक्रम समाज को सकारात्मक दिशा देते हैं। इस प्रकार यह बजट अपराध नियंत्रण को केवल दंडात्मक दृष्टि से नहीं, बल्कि संरचनात्मक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखता है। समग्र रूप से राजस्थान बजट 2026-27 यह स्पष्ट संदेश देता है कि सरकार विकास को सुरक्षा से अलग नहीं मानती। आधुनिक पुलिसिंग, तकनीकी सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, सामुदायिक सहभागिता और पुलिस कल्याण आदि सभी आयामों के माध्यम से प्रदेश में एक सुरक्षित, स्थिर और निवेश-अनुकूल वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया गया है।

इन घोषणाओं के समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन से राजस्थान न केवल आर्थिक प्रगति के मानकों पर, बल्कि कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी देश के अटाणी राज्यों में स्थान प्राप्त करेगा।

–ओ. पी. गल्होत्रा, महानिदेशक पुलिस (सैन।)

समृद्ध राजस्थान की ओर निर्णायक कदम है प्रदेश का बजट

सीए सुनील भागंव

राजस्थान का बजट 2026-27 आय-व्यय का औपचारिक दस्तावेज होने के साथ ही राज्य की विकास-दृष्टि का सुसंगठित घोषणापत्र है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में उपमुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री श्रीमती दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत यह बजट स्पष्ट संकेत देता है कि सरकार अल्पकालिक लोकलुभावन उपायों के बजाय दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से समृद्ध प्रदेश के संकल्प को साकार करना चाहती है। लगभग 6.11 लाख करोड़ रुपये के बजट आकार के साथ यह वित्तीय खाका विकास, सुशासन और सामाजिक संतुलन पर आधारित है।

राजकोषीय प्रबंधन की दृष्टि से यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने विकास व्यय में वृद्धि करते हुए भी वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है। राजकोषीय घाटे (79 हजार करोड़ से अधिक) का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का

3.69 प्रतिशत रहना यह दर्शाता है कि सरकार ने जिम्मेदार वित्तीय नीति को प्राथमिकता दी है। अनुमानित 21.52 लाख करोड़ रुपये का सकल घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के विस्तार की संभावनाओं को रेखांकित करता है।

किसी भी राज्य की समृद्धि का आधार उसका आधारभूत ढांचा होता है। बजट में सड़कों, फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज, बाईपास और राज्य राजमार्गों के विस्तार एवं उन्नयन के लिए 1800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह निर्माण कार्य आर्थिक गतिविधियों की गति बढ़ाने की रणनीति है। क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 1400 करोड़, अटल प्रगति पथ के लिए 500 करोड़ एवं राज्य राजमार्ग के लिए 2700 करोड़ से सड़कों की स्थिति बेहतर होगी। इंटरलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना और प्रमुख मार्गों पर आधुनिक निगरानी तंत्र का विस्तार शहरीकरण की चुनौतियों का तकनीकी समाधान प्रस्तुत करता है। इससे सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और पारदर्शिता में सुधार होगा।

पेयजल क्षेत्र में मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) के विस्तार और 5 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव राज्य की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है। बीसलपुर परियोजना से जलापूर्ति सुदृढ़ करने के लिए नई ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण दीर्घकालिक जल सुरक्षा का संकेत है। ऊर्जा क्षेत्र में 4,830 मेगावाट क्षमता के सौर पार्कों के विकास को योजना

राजस्थान को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्रीय अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह हरित विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता का संतुलित मॉडल प्रस्तुत करता है। राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए ‘प्लग एंड प्ले’ सुविधा, लॉजिस्टिक हब और इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना जैसे कदम उठाकर निवेश वातावरण को सुदृढ़ करने का संकेत दिया है। ~2024 के तहत मैनुफैक्चरिंग के साथ सेवा क्षेत्र को भी प्रोत्साहन देना औद्योगिक विस्तार की स्पष्ट दृष्टि को दर्शाता है। सरकार ने वर्ष 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य तभी संभव है जब निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को समानांतर गति दी जाए और बजट में इन तीनों आयामों को स्पष्ट रूप से संबोधित किया गया है।

समृद्ध प्रदेश की परिकल्पना युवाओं की सहभागिता के बिना अधूरी है। चार लाख भर्तियों के संकल्प की दिशा में एक लाख से अधिक नियुक्तियाँ और निजी क्षेत्र में दो लाख से अधिक रोजगार सृजन का उल्लेख राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वर्तमान में 1.43 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन होना प्रशासनिक सक्रियता का संकेत है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित करेगा। शिक्षा क्षेत्र में 400 विद्यालयों को – स्कूलों

में उन्नत करने हेतु 1,000 करोड़ रुपये का निवेश गुणवत्ता सुधार का ठोस प्रयास है। आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब्स और डिजिटल मेंटॉरिंग कार्यक्रम यह संकेत देते हैं कि सरकार शिक्षा को तकनीकी नवाचार से जोड़कर भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना चाहती है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिक विश्राम गुहों और जेके लॉन हॉस्पिटल में 500 बेड के टॉवर के निर्माण हेतु बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्तावित है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए – कार्यक्रम और जिला स्तर पर मेंटल हेल्थ केयर सेल की स्थापना यह दर्शाती है कि सरकार स्वास्थ्य को केवल शारीरिक उपचार तक सीमित नहीं मानती। महिलाओं के लिए ऋण सीमा में वृद्धि, ‘नंद घर’ मॉडल की आंगनबाड़ियों का विस्तार और लक्षप्रति दीदी योजना सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में ठोस कदम हैं।

कृषि क्षेत्र में 11,300 करोड़ रुपये से अधिक की सिंचाई परियोजनाएँ और 50 हजार सौर पंप संयंत्रों की योजना किसान हितैषी दृष्टिकोण के रेखांकित करती है। 35 लाख से अधिक किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये के व्याज मुक्त फसली ऋण का प्रावधान ठाणीम अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगा। राज मिशन के माध्यम से कृषि उत्पादों को वैश्विक पट्टाचन दिलाने का प्रयास कृषि के मूल्य संवर्धन और निर्यात से जोड़ता है।

‘हरियालो-राजस्थान’ के अंतर्गत

10 करोड़ पौधा रोपण का लक्ष्य पर्यावरणीय प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जल संरक्षण के लिए 2.0 के तहत व्यापक निवेश और वन्यजीव संरक्षण हेतु परियोजना हरित विकास की व्यापक सोच को दर्शाती है। कार्बन क्रेडिट पायलट परियोजना और औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए निर्माण यह संकेत देते हैं कि औद्योगिक विकास को पर्यावरणीय संतुलन के साथ जोड़ा गया है।

व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर 100 सेवाओं की शुरुआत, मिनी ई-निच मॉडल और – जैसी पहलें प्रशासन को पारदर्शी, उत्तरदायी और डेटा-आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। बजट 2026-27 एक समग्र विकास दृष्टि प्रस्तुत करता है जिसमें अवसंरचना, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के बीच संतुलित तालमेल दिखाई देता है।

इस बजट से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार केवल घोषणाएँ नहीं, बल्कि परिणामोन्मुख नीतिगत ढाँचा स्थापित करना चाहती है। यदि प्रस्तावित योजनाओं का समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ, तो यह बजट राजस्थान को आर्थिक मजबूती के साथ सामाजिक समृद्धि की नई ऊँचाइयों तक ले जा सकता है। समृद्ध प्रदेश का संकल्प अब नीतिगत दस्तावेज में रूपान्तरित हो चुका है, अब परीक्षा उसके प्रभावी क्रियान्वयन की है।

–सीए सुनील भागंव, आर्थिक मामलों के जानकार

राजस्थान बजट 2026-27 : विकास की नई ऊंचाइयां और वित्तीय मजबूती का प्रमाण

डॉ. सुरेंद्रसिंह शेखावत

राजस्थान सरकार ने 2026-27 के लिए 6.11 लाख करोड़ रुपये (लगभग 6 लाख 10 हजार 956 करोड़) का बजट पेश किया है, जो पिछले बजट की तुलना में 42 प्रतिशत की अप्रत्याशित उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत इस बजट में राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार तेजी से बढ़ने का प्रमाण मिलता है-41.39 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अब यह 21.52 लाख करोड़ रुपये तक पहुँचने का अनुमान है। प्रति

व्यक्ति आय 1.67 लाख से बढ़कर 2.02 लाख रुपये हो गई है, जो सरकार ने इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाकर राज्य को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मजबूत स्थान दिलाया है। पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) इस बजट की सबसे मजबूत विशेषता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक का सर्वाधिक आवंटन किया गया है-सड़कों, पुलों, जल आपूर्ति और सौर ऊर्जा पर फोकसा उदाहरणस्वरूप, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नल जल पहुँचाने के लिए 6,800 करोड़ रुपये, बीकानेर और जैसलमेर में नए सोलर पार्क्स के लिए 3,000 करोड़ रुपये (विशेष रूप से 2,950 करोड़ का प्रावधान), और कुल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 3,427 करोड़ रुपये का प्रस्ताव। 42,000 किमी नई सड़कों का निर्माण, 6,500 गांवों में जल कनेक्शन, सिनल-लैंड रो शहर, पीपम आवास योजना का विस्तार, और डूनेज-सड़क लाइट जैसी योजनाएँ शामिल हैं।

केंद्र सरकार के 12.2 लाख करोड़ रुपये के कैपेक्स से प्रेरित होकर राजस्थान भी इंफ्रास्ट्रक्चर-

जबकि उद्योग और सेवाएँ क्रमशः 27 प्रतिशत और 46 प्रतिशत के आसपास हैं। सरकार ने इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाकर राज्य को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मजबूत स्थान दिलाया है।

पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) इस बजट की सबसे मजबूत विशेषता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक का सर्वाधिक आवंटन किया गया है-सड़कों, पुलों, जल आपूर्ति और सौर ऊर्जा पर फोकसा उदाहरणस्वरूप, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नल जल पहुँचाने के लिए 6,800 करोड़ रुपये, बीकानेर और जैसलमेर में नए सोलर पार्क्स के लिए 3,000 करोड़ रुपये (विशेष रूप से 2,950 करोड़ का प्रावधान), और कुल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 3,427 करोड़ रुपये का प्रस्ताव। 42,000 किमी नई सड़कों का निर्माण, 6,500 गांवों में जल कनेक्शन, सिनल-लैंड रो शहर, पीपम आवास योजना का विस्तार, और डूनेज-सड़क लाइट जैसी योजनाएँ शामिल हैं।

केंद्र सरकार के 12.2 लाख करोड़ रुपये के कैपेक्स से प्रेरित होकर राजस्थान भी इंफ्रास्ट्रक्चर-

लेड ग्रोथ को प्राथमिकता दे रहा है। इससे रोजगार सृजन होगा, निवेश आकर्षित होगा, और राज्य की आर्थिक क्षमता मजबूत होगी।

अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि और कैपेक्स बढ़ोतरी से राज्य की समग्र प्रगति स्पष्ट है। राइजिंग राजस्थान माध्यम से 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश आकर्षित हुए, जिनमें से 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स बाउंड पर हैं। यह डबल इंजन सरकार की सफलता है। कृषि क्षेत्र में 25,000 करोड़ रुपये के व्याज-मुक्त ऋण, युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में 30,000 युवाओं को 10 लाख तक व्याज-मुक्त लोन, 400 इन्ोवेटिव स्कूल, होमगार्ड में 5,000 नए पद, और फ्री इलाज जैसी योजनाएँ आमजन की सेवा में सरकार की प्रतिबद्धता दिखाती हैं। एमएफएमई, पर्यटन, और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस से राज्य को ऊर्जा सुरक्षा और रोजगार का हब बनाया जा रहा है।

फिस्कल डिसिप्लिन बनाए रखते हुए यह विकास संभव हुआ है। राजस्व प्राप्तियाँ मजबूत हुई हैं-केंद्रीय करों

से 90,445 करोड़ रुपये प्राप्त। फिस्कल घाटा नियंत्रित स्तर पर हैं, जबकि कैपेक्स बढ़ रहा है। पिछले वर्षों में राजस्व घाटा जीएसडीपी का 1.6-1.9 प्रतिशत रहा, जो बेहतर प्रबंधन दर्शाता है। सरकार ने उधार को उत्पादक उपयोग में लगाया, जिससे भविष्य में व्याज बोझ कम होगा और विकास डिफाउट बनेगा।

यह बजट युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के लिए आशा की किरण है। 100 से अधिक योजनाएँ, रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण और समवेशी विकास को मॉडल पेश करता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर चल रही है। यह बजट राजस्थान को विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से ले जाएगा और 2029 में राज्य की 350 बिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की तत्पर तेज कदम होगा।

लेखक राजस्थान भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं।

- डॉ. सुरेंद्रसिंह शेखावत

प्रदेश में मा. शि. बोर्ड की परीक्षायें शुरु

पहले दिन सैकेण्डरी की अंग्रेजी अनिवार्य तथा सीनियर सैकेण्डरी की मनोविज्ञान की परीक्षा हुई

अजमेर, (कासं)। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित बोर्ड परीक्षाओं की गुब्बारा से औपचारिक शुरुआत हो गई। पहले दिन सैकेण्डरी में अंग्रेजी अनिवार्य तथा सीनियर सैकेण्डरी में मनोविज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित की गई। कक्षा 10वीं की अंग्रेजी विषय की परीक्षा देकर बाहर आए विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली रही, कई छात्रों ने प्रश्नपत्र को सरल बताया, जबकि कुछ ने इसे थोड़ा कठिन करार दिया। परीक्षा केंद्रों के बाहर विद्यार्थियों में हल्की घबराहट के साथ-साथ संतोष भी देखने को मिला। अधिकांश छात्राओं का कहना था कि प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम के अनुसार था और समय पर पूरा हो गया। वहीं कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि प्रामाण और रीडिंग सेक्शन के कुछ प्रश्न अपेक्षाकृत कठिन थे, जिनमें सोचने में अधिक समय लगा।

इधर, बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्थाओं को लेकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव गजेन्द्र सिंह राठौड़ स्वयं सक्रिय नजर आए। उन्होंने बोर्ड परिसर में संचालित कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और विभिन्न परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाओं की



प्रदेश के कई परीक्षा केंद्रों पर गुरुवार को 10वीं व 12वीं की परीक्षा हुई।

समीक्षा की। बोर्ड सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता और अनुशासन के साथ संपन्न कराई जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या नकल की शिकायत न आए। बोर्ड सचिव गजेन्द्र सिंह राठौड़ के अनुसार इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं के लिए 19 लाख 90 हजार 57 परीक्षार्थी

पंजीकृत हैं। प्रदेशभर में 6194 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। सुरक्षा और गिरगनी के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं तथा सवेदनशील केंद्रों पर विशेष नजर रखी जा रही है। कुल मिलाकर बोर्ड परीक्षाओं का पहला दिन सफल और शांतिपूर्ण रहा। अब आने वाले दिनों में अन्य विषयों की परीक्षाएं आयोजित

होंगी, जिनको लेकर विद्यार्थी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं।

वहीं नकल रहित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से गिरगानी की जा रही है। उड़नदस्तों और विशेष दलों की तैनाती की गई है। इस बार अभय कर्मांड सेंटरों के माध्यम से भी जिलों

- 10वीं की अंग्रेजी विषय की परीक्षा देकर बाहर आए कई छात्रों ने प्रश्नपत्र को सरल बताया, जबकि कुछ ने इसे थोड़ा कठिन करार दिया

- बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्थाओं को लेकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव गजेन्द्र सिंह राठौड़ सक्रिय नजर आए

के परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग की जा रही है। बोर्ड परिसर में परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व बोर्ड प्रशासक एवं संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ तथा सचिव गजेन्द्र सिंह राठौड़ सहित अधिकारियों ने विधिवत पूजा-अर्चना की और सीसीटीवी कक्ष व कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों को सघन जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया।

उदयपुर : सिलाई कर रही महिला पर चाकू से हमला , हालत गंभीर

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर जिले के कुराबड थाना क्षेत्र में बुधवार दे रात सिलाई का काम कर रही एक महिला पर अज्ञात बदमाश ने चाकू से हमला कर दिया। महिला गंभीर घायल हो गई, जिसके बाद उसे एमबी हॉस्पिटल रेफर किया गया। खून ज्यादा बहने से महिला की हालत गंभीर बनी हुई है।

हॉस्पिटल में भर्ती घायल महिला ने बताया कि हमले के दौरान वह चिल्लाती हुई दुकान से बाहर आई और लोगों से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन लोग तमाशे की तरह देखते रहे। किसी ने मेरी मदद नहीं की। थानाधिकारी तेजु सिंह ने बताया कि कुराबड के ब्रह्मपुर में यासमीन (35) पुत्री फैजाना शाह अपनी दुकान पर सिलाई कर रही थी। तभी अज्ञात व्यक्ति ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। महिला घायल हो गई, जिसका इलाज जारी है। पुलिस आसपास सीसीटीवी खंगालते हुए आरोपी की तलाश में जुटी है।

जाकाराी अनुसार आरोपी अपने बहन के कपड़े सिलाई के बाद लेने की बात कह रहा था, लेकिन पीड़िता ने ऐसे कोई कपड़े होने से इंकार कर दिया। इसके बाद आरोपी वहां से चला गया।

- बदमाश ने महिला की गर्दन, सिर और हाथ पर तीन वार किए
- पुलिस आसपास सीसीटीवी खंगालते हुए आरोपी की तलाश में जुटी

फिर करीब 20 मिनट बाद वापस लौटा और सिलाई करती महिला पर चाकू से हमला कर दिया। बदमाश ने महिला की गर्दन, सिर और हाथ पर तीन वार किए। जिससे वह घायल हो गई। आरोपी मौके से फरार हो गया। आसपास लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर कुराबड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस घटना के स्पष्ट कारणों की तलाश में जुटी है। घायल महिला की मामी गुलनाज बानो के अनुसार आरोपी ने यासमीन पर तीन बार चाकू से वार किए। मौके पर लोग जमा हो गए थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। हम घायल को हॉस्पिटल लाए तब भी पुलिस साथ नहीं थी।

उदयपुर, (कासं)। शहर के सविना थाना पुलिस ने महिला दुकानदार को चाकू दिखा उसके गले से सोने की चेन छीनने के मामले में पहाड़ा थाने के शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया।

प्रकरण के अनुसार 11 फरवरी को पीड़िता सुनिता पत्नी बन्नीलाल कलाल निवासी तीतरड़ी अम्बामाता घाटी सविना ने पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया कि मेरी गायत्री किरणा स्टोर पर शाम को मुंह बांध कर दो लड़के आए तथा सिगरेट लेने के बहाने बातचीत करते हुए मेरी गर्दन पर झपट्टा मार कर सोने की चेन छीन कर भाग रहे थे। इसको देख चिल्लाने पर लोगों ने घेरा डाल कर पकड़ लिया, लेकिन एक बदमाश चाकू दिखा कर बाइक से उतर कर फरार हो गया। डिटेन्शुदा बाल अपचारी की सूचना मिलने पर सविना थानाधिकारी गजवीरसिंह मय टीम ने जोगी तालाब 200 फीट रोड़ के समीप झाड़ियों में छिपा भवर लाल पुत्र लक्ष्मण लाल मीणा निवासी सैरफा फला बिचला पहाड़ा पुलिस को जांच की कर भागा जो गिरने पर चोटील होने पर चिकित्सालय में उपचार कराया। भवरलाल पहाड़ा थाने का बदमाश होकर उसके खिलाफ कई अपराधीक प्रकरण दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार था।

महिला की चेन छीनने वाला गिरफ्तार

बोरवेल खुदाई में निकली चांदी जैसी धातु लूटने पहुंचे लोग

अलवर, (निसं)। अलवर में बोरवेल करते समय चांदी जैसी धातु के टुकड़े निकले। यह सब देखकर सबसे पहले बोरवेल करने वाले मजदूर ही पत्थर लूटने लगे। इसके बाद आसपास के दुकानदार और लोग भी धातु के टुकड़े ले गए। मामला अरकापुरी इलाके में गुरुवार को करीब 1:30 बजे का है। यह बोरवेल जलदाय विभाग की ओर से करवाया जा रहा है। फिलहाल काम को रोक दिया है।

बोरवेल कर रहे मजदूर शाहरुख खान ने बताया कि यहां से लोग करीब 10 से 15 किलो वजन के चांदीनुमा पत्थर ले गए। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है कि जमीन के नीचे से आए चमकीले पत्थरों में चांदी कितनी प्रतिशत है। बोरवेल करते समय करीब 800 फीट तक मशीन से खुदाई हुई तो पानी-मिट्टी के प्रेशर के साथ नीचे जमीन से चांदी जैसी धातु के पत्थर निकले।

मजदूर शाहरुख खान ने बताया कि यहां 800 फीट गहरा बोरवेल करना था। इसमें आखिरी में जमीन की 20 फीट खुदाई तक मशीन पहुंची, तब यह चमकीला पत्थर निकलने लगा। आम तौर पर बोरवेल के नीचे से अलग-अलग तरह के पत्थर आ जाते हैं, लेकिन यह कुछ अलग है। इसमें धातु हो सकती है। आखिरी में करीब 5 से 10 प्रतिशत ऐसा पत्थर आया है। मशीन पर काम

सीमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला

बीकानेर, (निसं)। जिले के सीमावर्ती क्षेत्र छतरगढ़ में एक बार फिर पाकिस्तानी गुब्बारा दिखाई दिया है। पहले भी कई बार ऐसे ही गुब्बारे सीमावर्ती क्षेत्र में मिले हैं, जिन पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाईंस लिखा हुआ है। गुब्बारा मिलने की सूचना मिलते ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना कर दी।

छतरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने गुब्बारे की स्थिति, उस पर लिखे शब्दों और उसके आसपास के क्षेत्र की बारीकी से जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह पहली बार नहीं है जब छतरगढ़ या बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में इस तरह के गुब्बारे मिले हों। इससे पहले भी कई बार बॉर्डर इलाके में पाकिस्तान की ओर से भेजे गए गुब्बारे बरामद हो चुके हैं। कई बार इन गुब्बारों पर अलग-अलग कंपनियों, संस्थानों या पाकिस्तान से जुड़े नाम भी लिखे मिले हैं। सीमा पार से ऐसे गुब्बारे अक्सर सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान भटकाने, क्षेत्र में भ्रम फैलाने या किसी संदिग्ध गतिविधि को अंजाम देने की संशा से भेजे जाते हैं। ऐसे मामलों में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो जाती हैं क्योंकि कई बार इन गुब्बारों के साथ संदिग्ध सामग्री, संदेश या तकनीकी उपकरण भी जुड़े हो सकते हैं। पुलिस का कहना है कि फिलहाल गुब्बारे की जांच की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर इसे सुरक्षा एजेंसियों व विशेषज्ञ टीम को सौंपा जाएगा।

राजस्थान-सरकार	
	Office of the Medical Superintendent RUHS Hospital, Jaipur Sector-11, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Jaipur-302033 Ph. 0141-2792253 Email: supdt.hms@ruhsraj.org Date: 09/02/2026
No. RUHS/HMS/Manpower/2025-26/13922	
अल्पकालीन ई निविदा सूचना	
राज.स्वा.वि.वि.आयुर्विज्ञान चिकित्सालय में कार्य की प्रकृति के आधार पर अकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल मैन पावर सेवाओं के उपापन हेतु निर्धारित दर सविदा प्रपत्र अनुसार ई उपापन प्रक्रिया के अन्तर्गत ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। (कुल अनुमानित लागत राशि रु. 600 लाख)	
1. Bid Download Start Date/Time	09/02/2026 from 05:00 PM onwards
2. Bid Submission Start Date/Time	09/02/2026 from 05:00 PM onwards
3. Bid Submission End Date/Time	06/03/2026 at 02:00 PM
4. Technical Bid Opening Date/Time	07/03/2026 at 02:00 PM
* Details may be seen in the bidding document at https://eproc.rajjasthan.gov.in or https://sppp.rajjasthan.gov.in	
UBN: CMS2526SLRC00115	Medical Superintendent RUHS Hospital, Jaipur
Raj.Samwadi/C/25/19737	

राजस्थान-सरकार	
कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान आबकारी भवन-2 गुमानियावाला, पंचवटी, उदयपुर-313001 क्रमांक-F.32(B)(After Policy 2026-27)/ex/1/2026-06481-9018219/693	
दिनांक-11.02.2026	
कम्पोजिट रिटेल ऑफ मदिरा दुकानों के वर्ष 2025-26 के अनुज्ञाधारियों को वर्ष 2026-27 के लिये अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण के लिये आवेदन (विकल्प प्रस्तुत करने की नियत तिथि को बढ़ाई जाने की सूचना)	
इस कार्यालय की समस्तखक विज्ञापित क्रमांक 665 दिनांक 28.01.2026 के सन्दर्भ में राज्य के कम्पोजिट रिटेल ऑफ मदिरा दुकानों के वर्ष 2025-26 के समस्त अनुज्ञाधारियों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2026-27 के समस्त अनुज्ञाधारियों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2026-27 के लिए अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण के लिए पात्र एवं इच्छुक अनुज्ञाधारी अपना नवीनीकरण आवेदन (विकल्प) पत्र मय निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ दिनांक 16.02.2026 तक संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। दिनांक 16.02.2026 तक नवीनीकरण आवेदन (विकल्प) प्राप्त नहीं होने पर अनुज्ञाधारी का नवीनीकरण कर्वाण को विकल्प समाप्त हो जावेगा। तथा दुकान/समूह (Cluster) का आवेदन ई-नीलामी/ई-निविदा द्वारा किया जाएगा। वर्ष 2026-27 हेतु अनुज्ञापत्र नवीनीकरण से संबंधित समस्त जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट https://iems.rajjasthan.gov.in का अवलोकन करें। अन्य सभी भर्त पूर्तानुसार यथावत रहेंगे।	
आबकारी आयुक्त, राजस्थान	
DIPRC/	/2026

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER

PHED DIVISION KARAULI

PHNO.-07464-250219

E-Mail-ee.kar.phed@rajasthan.gov.in

Notice Inviting Bid

Bids for various works under summer contingency are invited from interested bidders up to 24.02.2026 other particulars of the bid may be visited eproc.rajjasthan.gov.in and sppp.raj.nic.in website. on the procurement portal

NIB CODE:-PHE2526A5986

S.N.	NIT NO.	UBN	S.N.	NIT NO.	UBN
1	142/2025-26	PHE2526WSOB12758	9	150/2025-26	PHE2526WSOB12771
2	143/2025-26	PHE2526WSOB12759	10	151/2025-26	PHE2526WSOB12773
3	144/2025-26	PHE2526WSOB12762	11	152/2025-26	PHE2526WSOB12774
4	145/2025-26	PHE2526WSOB12763	12	153/2025-26	PHE2526WSOB12776
5	146/2025-26	PHE2526WSOB12765	13	154/2025-26	PHE2526WSOB12777
6	147/2025-26	PHE2526WSOB12766	14	155/2025-26	PHE2526WSOB12779
7	148/2025-26	PHE2526WSOB12769	15	156/2025-26	PHE2526WSOB12780
8	149/2025-26	PHE2526WSOB12770	16	157/2025-26	PHE2526WSOB12781
01	Total work		16		
02	Total Estimate Cost		63.29 Lac		
03	Bid submission end date		24.02.2026 up to 06.00 PM		
04	Bid opening date		25.02.2026 at 02.00 PM		
(Vijay Kumar Meena) Executive Engineer PHED Division Karauli					

DIPRC/C/2411/2026

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (एम.एम.-प्रथम) पुराना पॉवर हाउस, बनीपार्क, जयपुर टेलीफ़ैक्स: 0141-2208098	
निविदा सूचना	
एल टी एक्स एल पी ई इंसुलेटेड एरियल बन्ड केबल, बेयर मेसेन्जर वायर के साथ (1Cx2x+25 Sq.mm) किलो संख्या- 5071) (UBN- VVN2526GLOB00979), 2 कोर एलटी पीपीसी आरएमड कोरल (2Cx4 Sq.mm) (निविदा संख्या-5072) (UBN- VVN2526GLOB00980), ए सी एस आर डोंग कंवक्टर (निविदा संख्या-5073) (UBN- VVN2526GLOB00981), फ़ैबीकोटेड स्टील आइटम (ब्लैकड) 33 केवी कॉस आर्म्स मय क्लैम्प (एंगल) व टॉप हैम्पर, 11 केवी कॉस आर्म्स (65x65x6) मय क्लैम्प (एंगल) व टॉप हैम्पर, 11 केवी टॉप हैम्पर बिना क्लैम्प, एलटी कॉस ब्रेकेट 4" लम्बे एवं 2" लम्बे, (निविदा संख्या-5074) (UBN- VVN2526GLOB00983), 33 केवी जी आई पिन (निविदा संख्या-5075) (UBN- VVN2526GLOB00982), 11 केवी पिन इन्सुलेटर (पॉलीमर) (निविदा संख्या-5076) (UBN- VVN2526GLOB00984), 11 केवी पिन इन्सुलेटर (पॉलीमर) (निविदा संख्या-5077) (UBN- VVN2526GLOB00985), 45 के एन टी एण्ड सी टाइप टाइप ड्रिफ्ट इन्सुलेटर (पॉलीमर) (निविदा संख्या-5078) (UBN- VVN2526GLOB00986), 11 केवी हॉर्न गैंग फ्यूज सैट पोस्ट इन्सुलेटर के साथ (निविदा संख्या-5079) (UBN- VVN2526GLOB00987), 33 केवी एवं 11 केवी आईसोलेटर के फिक्स्ड कॉन्टैक्ट (जॉ) एवं मुविंग कॉन्टैक्ट (पाइप) (निविदा संख्या-5080) (UBN- VVN2526GLOB00988) की खरीद हेतु ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली के अन्तर्गत निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा के बोके में अन्य विवरण वेबसाइट www.eproc.rajjasthan.gov.in एवं http://energy.rajjasthan.gov.in/jvnl द्वारा जाने जा सकते हैं। भविष्य में निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन / तिथि बदले की जानकारी केवल वेबसाइट www.eproc.rajjasthan.gov.in एवं http://energy.rajjasthan.gov.in/jvnl पर उपलब्ध कराई जाएगी। जेबीआर-3121 (2026) एच.सं.वार / सी / 25 / 19727	
अधीक्षण अभियन्ता (एम. एम. प्रथम) बिजली विभागों के लिए टेंडर की नम्बर 1800 180 6507	

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर	
टाउन-नहौल डिक रोड, उदयपुर (राज.) 313001	
दुरभाष सं 0294-2421255, 2420013, Helpline no. 0294-2426262 वेबसाइट- www.mcdudipur.org	
क्रमांक:- एस्.को. / 2025.26 / 209 दिनांक:-10.02.26	
ई-बोली आमन्त्रण सूचना संख्या-ई- 01/ 2025-26	
नगर निगम उदयपुर द्वारा अल्पाहार, भोजन व पानी कैंपेर सलाई कार्य की दर सविदा हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा की अनुमानित लागत 30.00 लाख है। ऑनलाइन निविदा प्राप्त मिलने की प्रारंभ दिनांक 11.02.26 अंतिम दिनांक 23.02.26 तथा खुलने की दिनांक 24.02.26 रहेंगी।	
UBN No. UNP2526GLRC00150	आयुक्त नगर निगम, उदयपुर
राज.सं.वार / सी / 25 / 19723	

कार्यालय नगर पालिका हिण्डोली जिला - बून्दी (राज0)		
क्रमांक :- न0पाशि0/निर्माण / 2025-26 / 3265 दिनांक :- 09.02.2026		
ई-निविदा सूचना संख्या 22 / 2025-26		
नगर पालिका हिण्डोली द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु नगर पालिका हिण्डोली में पंजीकृत कार्यों के अनुसार स्वाम स्वतः के संवेद्यक एवं अन्य विभागों में पंजीकृत A.A.A. श्रेणी के संवेद्यकों से डी लिफ्टाका प्दति/ई-निविदा प्दति से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य की निविदा बेचे जाने की दिनांक 10.02.2026 से तथा अपलोड करने की दिनांक 10.02.2026 से दिनांक 23.02.2026 तक है। जिसकी कुल लागत 54.50 लाख है। निविदा भर्त आदि सम्पूर्ण विवरण http://sppp.raj.nic.in , http://eproc.rajjasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। NIB code :- DLB2526B1447		
Sr.No.	UBN No.	Tender Cost in lakh
1	DLB2526WSRC33761	24.96
2	DLB2526WSRC33762	29.54
राज.सं.वार / सी / 25 / 19697		प्रशासक अधिसाथी अधिकारी

कार्यालय नगर परिषद टोंक

क्रमांक :- न.प.टी.क./ निर्माण / 2025-26 / 14290 दिनांक :- 09.02.2026

NOTICE INVITING TENDERS THROUGH
NIT No 87 / 2025-26

Bids are invited from interested bidders from 10.02.2026 (10.00AM) to 23.02.2026 (6.00PM) as per following details. Other particulars of he bid may be visited on procurement portal (www.Sppp.Rajasthan.gov.in) of the state NIB No. DLB2526B1403

NIT No.	Name of work	UBN No.
87/2025-26	आईडीएरएफटी कॉलोनी मे सेक्टर नं. बी एवं सी के पार्क का सौन्दर्यकरण करने का कार्य (अनुमानित राशि 29.98 लाख)	DLB2526WSOB33593

Date & time of opening of tender 24.02.2026 at 3.00PM

अति जिला कलक्टर
एवं प्राधिकारी / प्रशासक

आयुक्त
नगर परिषद, टोंक

राज.सं.वार / सी / 25 / 19677 न0पाटी0क

राजस्थान सरकार वन विभाग	
कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा राजभवन रोड, सिविल लार्न्स, नयापुर, कोटा-324001 दूरभाष/फैक्स 0744-2322747 (ई मेल आई.डी. dcfl.kota.forest@rajasthan.gov.in)	
क्रमांक- एफ।1 स्टीर/असई/2025-26/890 दिनांक-01.02.2026	
ई-निविदा सूचना संख्या 48/2025-26	
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से MSME / SSI Unit / अधिकृत पंजीकृत निर्माताओं/ विक्रेताओं/सप्लायर्स से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आरएफबीडीपी योजनान्तर्गत इस कार्यालय के अधीन विभिन्न रेजो लाइपुरा, मण्डाना, मोडक, कनवास, सुल्तापुर, ईटावा एवं खालोली के क्षेत्राधिकारी अधीन राजकीय विद्यालयों हेतु विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था हेतु आयरन टेबल कम बेंचस को क्रय करने के लिए द्वि-स्तरीय निविदा प्रक्रिया के माध्यम से वार्षिक दर अनुबंध पद्धती के आधार पर ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।	
उक्त निविदा को ऑनलाईन भरने की अंतिम तिथि 15.02.2026 को सायं 06.00 बजे तक है। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण निम्नानुसार साईट्स परदेखा जा सकता है। https://sppp.rajjasthan.gov.in एवं www.eproc.rajjasthan.gov.in	
UBN NO. 1- FOR2526WSOB05315 (अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव) उप वन संरक्षक कोटा (राज.)	
DIPRC/2711/2026	

भारत-पाक बॉर्डर पर 10 करोड़ की हेरोइन मिली

बीकानेर, (निसं)। भारत-पाक बॉर्डर पर बीकानेर जिले के खाजुवाला क्षेत्र में एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से हेरोइन गिराई गई है। बॉर्डर से 2 किमी दूर मिला 2 किलो 25 ग्राम हेरोइन जो खाजुवाला के कार्यवाहक एसएसओ हरपाल सिंह ने बताया कि मंगलवार देर रात बॉर्डर के पास संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली थी। आशंका थी कि ड्रोन के जरिए मादक पदार्थ गिराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। रात करीब एक बजे चक 14 बीडी के पास बॉर्डर से करीब दो किलोमीटर दूर एक पीले रंग का पैकेट बरामद हुआ। जांच में उसमें करीब 2 किलो 25 ग्राम हेरोइन होने की पुष्टि हुई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। बरामद पैकेट में दो

- बीकानेर जिले के खाजुवाला क्षेत्र में ड्रोन से गिराई गई थी हेरोइन

छड़ें लगी हुई थी, जिन्हें संभवतः ड्रोन से जोड़कर गिराने के लिए इस्तेमाल किया गया। शुरुआती जांच में साफ है कि तस्करों ने ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर सीमा पार से खप भेजी। पुलिस ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ थाना प्रभारी समरवीर को सौंपी है। आसपास के क्षेत्र में सर्वे ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खाजुवाला क्षेत्र में यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले 8 जनवरी को चक 40 केजेडी में भी पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गिराई गई करीब छह करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई थी। उस समय 500 ग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी।

ट्रेन की चपेट से युवक की मौत

बयाना/भरतपुर, (निसं)। बयाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना रुदावल थाना क्षेत्र के ब्रह्मबाद रेलवे फाटक के पास की बताई जा रही है। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जानकारी ली।

जानकारी के अनुसार युवक रेलवे पटरी पार कर रहा था, तभी अचानक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही बंध बरोटा थाना इंचार्ज भरतलाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रुदावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक की पहचान सुरेंद्र शर्मा पुत्र भूदेव निवासी गांव ककलपुरा के रूप में हुई है। पुलिस ने परिजनों की सूचना दे दी है और आगे की कार्रवाई जारी है। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है।

‘‘राइट टू हैल्थ’’ एक्ट पर विधानसभा में सत्ता पक्ष व विपक्ष में घमासान

सरकार का कहना था कि मौजूदा योजनाओं में स्वास्थ्य का अधिकार मिल रहा है, अलग कानून की जरूरत नहीं

जयपुर, 12 फरवरी। राजस्थान विधानसभा में गुरूवार को प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम-2०22 (राइट टू हेल्थ) को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और जोरदार हंगामा देखने को मिला। सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

विधायक हरिमोहन शर्मा ने, अप्रैल 2०23 में अधिसूचित राइट टू हेल्थ एक्ट के नियम अब तक लागू नहीं किए जाने पर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने पूछा कि नियम क्यों नहीं बनाए गए, प्राप्त सुझावों पर क्या निर्णय हुआ और इस संबंध में हुई बैठकों का ब्यौरा क्या है? साथ ही, उन्होंने हाईकोर्ट के नोटिस

- कांग्रेस का कहना था कि नियम नहीं बना कर जनता के **स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉक आउट किया।**

और सरकार के जवाब की जानकारी भी मांगी।

इस पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खीवरसर ने कहा कि पिछली सरकार चुनाव से ठीक पहले बिना पर्याप्त तैयारी के यह अधिनियम लेकर आई थी। नियम नहीं बनाए गए और हितधारकों से समुचित चर्चा भी नहीं की गई। उन्होंने बताया कि अधिनियम के नियमों को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल लंबित है और निर्णय प्रतीक्षित है।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही “मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (मा) योजना” के तहत 25 लाख रुपये तक का वार्षिक कैशलेस इलाज उपलब्ध करा रही है। योजना के तहत 1.36 करोड़ पात्र परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है और 217.9 उपचार पैकेज इसमें शामिल हैं। निःशुल्क जांच, दवाइयां, ओपीडी, आर्इपीडी, आपातकालीन सेवाएं, हीमोडायलिसिस और एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं पहले से दी जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को बता दिया है कि फिल्म का नाम बदला जा रहा है और टेलर तथा प्रचार सामग्री पहले ही वापस ले ली गई है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्माताओं से यह भी बताने को कहा कि क्या फिल्म “घूसखोर पंडित” में किसी समुदाय के प्रति आपत्तिजनक सामग्री दिखाई गई है।
कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं से इस संबंध में हलफनामा भी मांगा है।
अदालत ने, “फ्राईडे फिल्मवक्स” द्वारा निर्मित इस फिल्म की टीम को फटकार लगाते हुए पूछा कि फिल्म निर्माता संयम क्यों नहीं बरत सकते।

बेअसर रहा भारत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
की सभी ट्रेड यूनियनं, किसान और मजदूर मोदी सरकार के व्यापार समझौते, श्रम कानूनों और मनरेगा को समाप्त करने के खिलाफ सड़कों पर हैं।
ओडिशा, केरल, तमिलनाडू, गोवा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब सहित, कई राज्यों में मिला-जुला असर देखने को मिला।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने मजदूरों और किसानों के भविष्य से जुड़े निर्णय लेते समय उनकी

आवाजों को नज़रअंदाज किया।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच से जुड़े कर्मचारियों और मजदूरों ने आज दिनभर की हड़ताल कर केन्द्र सरकार की मजदूर-विरोधी, किसान-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी कार्रगोरेट समर्थक नीतियों के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया। मंच ने दावा किया कि नई श्रम संहिताओं सहित, अन्य मुद्दों के विरोध में सामान्य हड़ताल के लिए 3० करोड़ मजदूरों को संगठित किया जा रहा है।

कक्षा-1० ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
परीक्षा 2०26 के लिए बड़े बदलाव किए हैं, जिनमें प्रश्नपत्र प्रारूप में संशोधन और वर्ष में दो बार परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था शामिल है।

विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्नपत्रों में अब स्पष्टता और मूल्यांकन मानकों में सुधार के लिए नए खंडीय प्रारूप (सेक्शनल फॉर्मेट) का पालन किया जायेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2०2० के अनुरूप, कक्षा 1० की बोर्ड परीक्षाएं अब वर्ष में दो बार आयोजित की जाएंगी।

इस प्रणाली के तहत, विद्यार्थियों को अपने अंक सुधारने या जिन विषयों में वे फेल हुए हैं उन्हें पास करने के लिए दोबारा परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। इस योजना के अनुसार, छात्र दूसरी परीक्षा में अधिकतम तीन विषयों में सुधार परीक्षा दे सकते हैं, जो 15 मई से 1 जून 2०26 तक होनी है।

सीबीएसई की सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी बोर्ड परीक्षाएं 2०26, 17 फरवरी से शुरू होंगी। ये परीक्षाएं भारत और विदेश के 26 देशों में स्थित 31,०0० से अधिक संबद्ध विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाएंगी। कक्षा 1० की परीक्षा में सबसे पहले गणित (स्टैंडर्ड और बैसिक) विषय का पेपर होगा।

मोदी आज नए ऑफिस ‘सेवा तीर्थ’ में शिफ्ट होंगे

नई दिल्ली, 12 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 फरवरी को नए प्रधानमंत्री ऑफिस ‘सेवा तीर्थ’ में शिफ्ट होंगे। जानकारी के अनुसार, मोदी दोपहर करीब 1:3० बजे ‘सेवा तीर्थ’

- सेवा तीर्थ के साथ ही कर्तव्य भवन-1 और 2 का भी शाम 6 बजे उद्घाटन होगा।**

बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के नाम का अनावरण करेंगे।फिर शाम करीब 6 बजे सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन-1 और 2 का उद्घाटन करेंगे।

इसके बाद, पीएम एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। कर्तव्य भवन-1 और 2 में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों के नए ऑफिस होंगे। वर्तमान में पीएमओ और मंत्रालयों के ऑफिस नई दिल्ली स्थित सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में हैं।

‘दिल्ली हवा खाने नहीं आए हैं’, राजनीति करने आए हैं’ कर्नाटक के नेता शिवकुमार ने दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए टिप्पणी की

- डी के शिवकुमार ने खड़गे, सोनिया, राहुल और प्रियंका से मुलाकात की।**

- शिवकुमार की इस मीटिंग के बाद एक बार फिर कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा शुरु हो गई है।**

हालांकि शिवकुमार ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड़ा से मुलाकात पर सीधा जवाब नहीं दिया। शिवकुमार की इस मुलाकात के बाद कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लगाई जा रही है।

‘दूषित फल-सब्जियों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
अदालत ने पूछा कि राज्य सरकार यह कैसे सुनिश्चित करती है कि डेयरियों में पहुंचा हुआ दूध मिलावटी नहीं है। इस दौरान पूर्व महाधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि पशुओं को ऑक्सिटीसीन इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे दूध उत्पादन

तालेड़ा के स्कूल में स्ट्रीट डॉग्स ने बालिका पर हमला किया

बालिका के दादा के अनुसार, उसके चेहरे को छोड़कर पूरे शरीर पर घाव हैं

- कोटा मैंडिकल कॉलेज में सर्जरी के एचओडी डॉ. नीरज देवेंदा ने बताया कि बालिका के शरीर पर करीब 20 घाव हैं। उसके फेफड़ों तक में घाव हो गया, इसलिए श्वसन तंत्र को सुचारु रखने के लिए ट्यूब डाली गई है।**

गए, जहां से बच्चों को कोटा रेफर किया गया है।

बालिका के दादा भंवरलाल सेन का कहना है कि वे लोग सीतापुरा रहते हैं। वहीं से बालिका स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में पढ़ने तालेड़ा जाती थी, जहां पर यह घटना हुई है। उन्होंने बताया कि स्ट्रीट डॉग्स ने बालिका को इतनी बुरी तरह काटा है कि उसके शरीर पर चरेरे को छोड़कर लगभग सभी जगह पर घाव हो गए हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल में वे वैन से कई बार बच्चों को

लेने भी जाते हैं, तब बड़ी संख्या में स्ट्रीट डॉग्स स्कूल में घूमते नजर आते हैं। उन्होंने कहा, सरकार तत्काल इस पूरे प्रकरण पर संज्ञान ले। मेडिकल कॉलेज कोटा में सर्जरी के एचओडी डॉ. नीरज का कहना है कि बालिका के शरीर पर करीब 2० के आसपास घाव हैं। उसके फेफड़ों तक में भी घाव हो गया है। इसीलिए ट्यूब डाली गई है, ताकि बालिका के श्वसन तंत्र को सुचारु रखा जा सके।बालिका के हाथ, पैर और छाती सहित, कई जगह पर घाव के निशान हैं।

भारत में निपाह वायरस से पहली मौत

नई दिल्ली, 12 फरवरी। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस से संक्रमित दो मरीजों में से एक मरीज की मौत हो गई है। देश में इस साल निपाह वायरस से यह पहली मौत है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि 11 जनवरी 2०26 को पश्चिम बंगाल से रिपोर्ट किए गए निपाह संक्रमण के दो

संक्रमित नर्सिंग स्टाफ नॉर्थ 24 पराना जिले के बारासात के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थे। इनमें एक पुरुष नर्स और एक महिला नर्स शामिल थीं। पुरुष नर्स इलाज के दौरान ठीक हो गया, लेकिन महिला को उपचार के दौरान मौत हो गई।

बांग्लादेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
महिलाओं को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है, वहीं प्रमुख दलों ने भी उन्हें केवल औपचारिक या प्रतीकात्मक नामांकन दिए हैं। 2०26 के चुनाव महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में स्पष्ट और जबरदस्त गिरावट दर्शाते हैं और बांग्लादेश की राजनीति में लैंगिक समानता के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। गुरुवार को चुनाव के दिन ढाका में भारी मतदान देखा गया, जहां जमात और बीएनपी के बीच मुकाबला चुनावी परिदृश्य को परिभाषित करता नजर आया। जनरेशन-ज़ैड आंदोलन के बाद हो रहे इस पहले चुनाव में जमात और बीएनपी समर्थकों के बीच झड़पों की भी खबरें सामने आईं।

श्रीलंका के लिए हवाई उड़ानों के किराए में भारी वृद्धि

भारत-पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को कोलम्बो में होने वाले मुकाबले के कारण यह वृद्धि हुई है

- बड़ी संख्या में लोग कोलम्बो जा रहे हैं इस वजह से चेन्नई से कोलम्बो की हवाई टिकट, जो 7,127 रुपये की होती थी, के दाम बढ़कर 22 से 25 हजार तक पहुँच गए हैं।**

किराया सामान्यतः कम रहता है। इसी वजह से चेन्नई से श्रीलंका जाने वाले यात्रियों की संख्या आमतौर पर अधिक रहती है।

सामान्य दिनों में चेन्नई-श्रीलंका के बीच हवाई किराया लगभग 7,127 रुपये होता है, लेकिन 13 तारीख को इंडिगो एयरलाइंस की इकोनॉमी क्लास का किराया 22,073 रुपये से 25,2०7 रुपये तक पहुंच गया है, जबकि श्रीलंकन एयरलाइंस का किराया

42,231 रुपये तक हो गया है।

14 तारीख को इंडिगो एयरलाइंस का किराया 2०,7०8 रुपये से 25,2०7 रुपये तक और श्रीलंकन एयरलाइंस का किराया 35,217 रुपये तक बढ़ गया है। मैच के दिन यानी, 15 तारीख को इंडिगो एयरलाइंस में किराया 18,283 रुपये से 19,464 रुपये तक और श्रीलंकन एयरलाइंस में 28,66० रुपये से 42,231 रुपये तक निर्धारित किया गया है।

नार्थ कोरिया के किम जोंग उन ने अपनी बेटी को वारिस बनाया

व्योंगयांग, 12 फरवरी। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने अपनी बेटी जू-ए को अपना वारिस चुन लिया है। साउथ कोरिया की जासूसी एजेंसी (एनआईएस) ने गुरुवार को देश के संसदों के सामने यह दावा किया। नेशनल इंटे्लिजेंस सर्विस (एनआईएस) ने कहा कि उनके इस दावे के पीछे कई चीजों को आधार बनाया गया है। इनमें उत्तर कोरिया के सरकारी कार्यक्रमों में जू ऐ की बढ़ ती उपस्थिति एक अमर वजह है। इससे लगता है कि किम ने अपने वारिस पसंदा ले लिया है। एनआईएस ने कहा है कि उनकी इस पर नजर होगी कि जू-ए इस महीने के आखिर में नॉर्थ कोरिया की पार्टी कांग्रेस में शामिल होंगी या नहीं। यह बड़ा पॉलिटिकल इवेंट पांच साल में एक बार होता है। टीनएज जू-ए का इस कार्यक्रम में आना इस बात की तस्दीक होगी कि वे इस सालने वाली अपनी परिवार की चौथी पीढ़ी बनने जा रही है।

करने के सीधे प्रयास को न केवल प्रक्रियात्मक और कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ता, बल्कि लोकतंत्र को कमजोर करने के विपक्षी दलों के आरोपों को भी बल मिल सकता था।

राहुल गांधी के लिए यह प्रकरण उनके विकसित होते संसदीय व्यक्तित्व को रेखांकित करता है, एक ऐसे नेता के रूप में, जो तीखे टकराव से पीछे नहीं हटता। यह रणनीति उन्हें दीर्घकालिक राजनीतिक लाभ देगी या नहीं, यह अभी देखना बाकी है। फिलहाल, जो विशेषाधिकार प्रस्ताव आसप्त प्रतीत हो रहा था, वह राजनीतिक दांव-पेंच और संसदीय व्यावहारिकता के टकराव का उदाहरण बन गया है।

निष्कर्षतः, यह प्रकरण समकालीन भारतीय राजनीति की इस व्यापक सच्चाई को उजागर करता है कि लड़ाईयाँ केवल सदन के पटल पर ही नहीं, बल्कि धारणा, गठबंधन प्रबंधन और चुनावी गणित के क्षेत्र में भी लड़ी जाती हैं और कभी-कभी सबसे महत्वपूर्ण कदम वही होता है, जो अंततः उठाया ही नहीं जाता।

करने की कोशिश की जाती है। डिजिटल युग में, अभिलेखों से हटाए गए अंश अक्सर आधिकारिक रिकॉर्ड से बाहर व्यापक रूप से प्रसारित हो जाते हैं, जिससे संसर्गश्रि का व्यावहारिक प्रभाव सीमित हो जाता है और राजनीतिक बहस और तेज हो जाती है।

इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय जांचों से जुड़े संभावित भविष्य के खुलासों से सम्बन्धित अटकलों ने राजनीतिक माहौल में अनिश्चितता का तत्व जोड़ दिया है। यद्यपि शीर्ष भारतीय नेतृत्व को फंसाने वाले किसी संभावित खुलासे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसी रिपोर्टों का प्रसार ही राजनीतिक हलकों में संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। ऐसे माहौल में संसदीय टकराव को बढ़ाना अनिश्चित परिणामों वाला दुःसाहस माना जा सकता था।

मोदी सरकार के सामने दृढ़ता और संयम के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती है। बिना किसी न्यायिक दोषसिद्धि या स्पष्ट संवैधानिक आधार के, नेता प्रतिपक्ष की सदस्यता समाप्त

पाकिस्तान को मिलने वाले सिंधु नदी के साझा पानी के प्रवाह पर गंभीर असर पड़ेगा, जिससे उसके देश के अस्तित्व से जुड़ा जल अधिकार प्रभावित होगा।

भारत द्वारा चिनाब नदी पर 5129 करोड़ रुपये की सावलकोट जलविद्युत परियोजना पर काम शुरू करने की खबरों के बाद पाकिस्तान सरकार ने सिंधु बॉर्डर्स कमिश्नर के स्तर पर चिंता जताई है और इस परियोजना से जुड़ी जानकारी और बातचीत की मांग की है।

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा, “सिंधु

के स्थाना के बाद केन्द्र सरकार से मंजूरी

पाने वाली पहली बड़ी नई परियोजना है। इसके अलावा, पाकल डुल, किरू और रतले बांध परियोजनाओं की भी शुरु करने की प्रक्रिया चल रही है। भारत सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से पानी के प्रवाह का बेहतर प्रबंधन होगा और देश की बिजली उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी।

पाकिस्तान भारत की इन कार्रवाइयों का विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि भारत द्वारा बांध बनाने से

कायदे, कानून व प्रक्रिया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इसे फर्जी ही कहा जा सकता है।

लेकिन सरकार की हर बात को दोहराने वाला सुविधाजनक गोदी मीडिया यह खबर चला रहा है कि राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया जाएगा। यह बात निश्चित रूप से हर उस भाजपा समर्थक के दिल और दिमाग में

- ‘‘डिस्क्वालिफिकेशन’’ करने के लिए कायदे-कानून व प्रक्रिया की पूरी जानकारी कान होना, फिर कार्रबा बना, राहुल गांधी को ‘‘डिस्क्वालिफाई’’ करने के प्रयास के असफल होने का।**

हो सकता है जो राहुल गांधी से नफरत करता है, और ऐसे लोग काफी संख्या में हैं। लेकिन बिना सही नियम और

राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
था कि गांधी के बयानों से संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक हुई है और इससे सशस्त्र बलों का मनोबल प्रभावित हो सकता है, और संसदीय संदर्भ में यह एक गंभीर आरोप है।

लेकिन शाम तक परिदृश्य बदलता दिखाई दिया। संसदीय सूत्रों ने संकेत दिया कि विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने, या अयोग्यता से संबंधित किसी प्रस्ताव को संस्थानत समर्थन नहीं मिला। संसदीय कार्यसूची में किसी औपचारिक उल्लेख का न होना इस बात का संकेत था कि इस कदम पर पुनर्विचार किया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि पीछे हटना कमजोरी नहीं, बल्कि रणनीतिक पुनर्संतुलन है। राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली होने के बावजूद, भाजपा के पास वर्तमान लोकसभा में ऐसा प्रचंड बहुमत नहीं है कि विपक्ष के नेता के खिलाफ विवादस्पद अनुशासनात्मक कार्रवाई आसानी से की जा सके। ऐसे किसी भी कदम के लिए, सदन प्रबंधन, सहयोगियों के साथ समन्वय और,

सबसे ऊपर, संभावित प्रतिक्रिया का राजनीतिक आकलन आवश्यक होता। एनडीए के व्यापक दायरे के सूत्रों के अनुसार, टीडीपी और जेडी (यू) जैसे प्रमुख सहयोगी दल ऐसे बड़े टकराव से असहज हो सकते हैं, क्योंकि इसे असहमित दबाने के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। आगामी महत्वपूर्ण राज्य विधानसभाओं चुनावों को देखते हुए, गठबंधन का गणित, वैचारिक स्थिति जितना ही महत्वपूर्ण है।

राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी अतिशयता पूर्ण कार्रवाई से विपक्ष को एकजुट होने का अवसर मिल सकता था और इस कार्रवाई से गांधी की राष्ट्रीय छवि के और मजबूत हो जाने की सम्भावना थी।

इसके अतिरिक्त, इस पूरी घटनाक्रम में छवि-प्रबंधन का पहलू भी महत्वपूर्ण है। किसी भाषण के हिस्सों को हटाना अध्यक्ष का एक प्रक्रियात्मक अधिकार है, लेकिन जब यह कदम विवादस्पद राजनीतिक आरोपों से जुड़ता है, तो कभी-कभी वही बात और अधिक फैल जाती है, जिसे नियंत्रित

माईन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हथ्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386०31, 2386०32,फैक्स:०744-2386०33, उदयपुर कार्यालय: आर्य मैन रोड आर्यड, उदयपुर। फोन: 2413०92, फैक्स : ०294-241०146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:०145-2624665, जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फैस प्रथम, जालौर। फोन: 226422,226423, फैक्स: ०2973-226424 डिण्डौरीनसी कार्यालय :- जी -1-2०1, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 23०200, 23०400, फैक्स: ०7469-23०600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 2569०6, 2569०7, फैक्स: ०1562-2569०8

